

(7)

न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ० भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 52/2019 G.C.M.S. No. 2019/00089 दर्ज दिनांक : 25.03.2019
अपीलार्थिगणः

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगणः

1. परबतसिंह पुत्र भैरूसिंह
2. रामसिंह पुत्र भैरूसिंह के विधिक वारिसानः-
2/1 छैल कंवर बेवा रामसिंह
2/2 भंवर कंवर पुत्री रामसिंह, जाति राजपूत, निवासी पांचलवाड़ा,
तहसील बाली जिला पाली।
3. झुंझारसिंह पुत्र भैरूसिंह फौत के विधिक वारिसानः-
3/1 प्रेमकंवर पुत्री जुंझारसिंह
3/2 सुमित्रा पुत्री जुंझारसिंह
3/3 सुमन पुत्री जुंझारसिंह
3/4 रघुनाथसिंह पुत्र जुंझारसिंह
3/5 दशरथसिंह पुत्र जुंझारसिंह
3/6 कृष्णपालसिंह पुत्र जुंझारसिंह
जाति राजपूत, निवासी पांचलवाड़ा, तहसील बाली जिला पाली।
4. छैलसिंह पुत्र भैरूसिंह
5. गुलाबसिंह पुत्र जालमसिंह फौत के विधिक वारिसानः-
5/1 फतेहसिंह पुत्र गुलाबसिंह
5/2 गोर्धनसिंह पुत्र गुलाबसिंह फौत के विधिक वारिसानः-
5/2/1 सुरज कंवर बेवा गोर्धनसिंह, जाति राजपूत,
5/2/2 डिम्यल कंवर पुत्री गोर्धनसिंह, जाति राजपूत
5/2/3 पहलवानसिंह पुत्र गोर्धनसिंह, जाति राजपूत
5/2/4 राजेन्द्रपाल पुत्र गोर्धनसिंह, जाति राजपूत, निवासी
पांचलवाड़ा, तहसील बाली जिला पाली।



अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 67/1987 बअनवान परबतसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.1993 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार-

1. श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना, विद्वान राजकीय पैरोकार अपीलान्ट।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री धीरेन्द्रसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्ष्णसिंह राजपुरोहित विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 01.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या पाली



67/1987 बअनवान परबतसिंह वगैरह बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.1993 के विरुद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है-

यह कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी महोदय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, जो रेकॉर्ड व मौके को नजरअंदाज करते हुए धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की किस्म बारानी दायम (गोचर) भूमि की खातेदारी दी गई हैं। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। जो प्रथमदृष्टया निरस्त करने योग्य है।

यह कि ग्राम पांचलवाड़ा तहसील बाली के गत खसरा नंबर 39 रकबा 32-13 बीघा से बने हाल खसरा नंबर 327 रकबा 4.20 हैक्टेयर व खसरा नंबर 329/503 रकबा 0.52 हैक्टेयर कुल रकबा 5.22 हैक्टेयर गोचर भूमि की श्रीमान उपखंड अधिकारी बाली के द्वारा रेस्पॉडेंट को जो खातेदारी देने का आदेश पारित किया गया है, जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत किया गया है, जिससे गांव में स्थित गोचर भूमि का रकबा कम होने से गांव के पशुओं के चराई में भारी समस्या उत्पन्न होगी। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमावें एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.1993 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाली में वादी रेस्पॉडेंट्स द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र अपीलांत के विरुद्ध दिनांक 29.07.1987 को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.1993 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 10.08.2018 को प्रस्तुत की। जो अपील के लिए विहित अवधि 60 दिवस के स्थान पर लगभग 25 वर्ष 2 माह अर्थात् लगभग 9185 दिवस के अत्यंत दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांत द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलाधीन गोचर भूमि को रेस्पॉडेंट संख्या 1 से 5 के नाम से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करने का पारित निर्णय दिनांक 28.04.1993 विधिविरुद्ध होने से एवं श्रीमान उपखंड अधिकारी बाली के आदेश


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

क्रमांक 2016/96 दिनांक 02.02.2016 की पालना में यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही हैं। उपरोक्त आदेश दिनांक 28.04.1993 की जानकारी अपीलांत भूमिधारी तहसीलदार को नहीं थीं। हाल ही में रेस्पॉडेंट द्वारा उपरोक्त खसरा नंबर की कृषि भूमि के बारे में पारित आदेश व नामांतरण भरने बाबत प्रार्थना पत्र पेश करने पर जानकारी में आया। जिस पर अपीलांत द्वारा बिना देरी के अपील पेश की गई। अतः अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्यायोचित है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पॉडेंट्स वादीगण के पूर्वज मुकनसिंह वल्द जालमसिंह की खुदकाशत जागीर भूमि थीं। जिसकी किस्म बारानी दायम अंकित है। अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात की जमाबंदी संवत 2064 से 2067 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि जमाबंदी का कॉलम संख्या 7 जो भूमि वर्गीकरण से संबंधित है तथा इसके आधार पर भूमि की किस्म निर्धारित होती हैं, में अपीलाधीन भूमि बारानी दायम अंकित है। अतः प्रथम तो तहसीलदार अपीलांत का यह कथन कि वादग्रस्त आराजीयात संबंधित गोचर भूमि है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पॉडेंट को गोचर भूमि में खातेदारी प्रदान की गई हैं, पूर्णतया अभिलेख के विपरीत, आधारहीन व मनगढ़ंत है। अपीलाधीन प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात अपीलांत के पूर्वज की खुदकाशत जागीर भूमि थीं तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की सुनवाई उपरांत विधिवत रूप से व अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जिसे विधिविरुद्ध या विधि की दृष्टि में शून्य निर्णय या डिक्री नहीं माना जा सकता।



4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पॉडेंट द्वारा अपीलांत के विरुद्ध प्रस्तुत वाद में अपीलांत की समुचित तामील एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। तत्पश्चात वादी रेस्पॉडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में डिक्री की इजराय हेतु प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 21 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 44/2009 प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत की सुनवाई उपरांत दिनांक 15.07.2015 को डिक्री की भू-अभिलेख में अमल दरामद करने बाबत आदेश पारित किया तथा पत्रांक 96 दिनांक 02.02.2016 द्वारा तहसीलदार अपीलांत को पालनार्थ प्रेषित किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपीलांत प्रार्थी को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.04.1993 की आरंभ से ही


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बखूबी जानकारी थीं। अतः प्रार्थी अपीलांत द्वारा यह कथन करना कि उन्हें अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी, महज काल्पनिक व आधारहीन कथन है।

5. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :-

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.



2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.

3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is preferred after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforesaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed



6. हमने माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 9185 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरुद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि 9185 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांत परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।



आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांत अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि जिला कलक्टर पाली व तहसीलदार बाली को पृथक से प्रेषित की जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ० भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली